भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1439

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**प्रासंगिक व्ययों को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना**

1439. श्रीमती माया सिंह:

 क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से खरीफ विपणन के प्रासंगिक व्ययों को अन्तिम रूप से निर्धारित करने हेतु वर्ष 2001 से अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन प्रस्तावों में प्रस्तावित कुल धनराशि कितनी है;

(ग) लंबित प्रस्तावों का विवरण क्या है और किन कारणों से प्रस्तावों को इतने लंबे समय से लंबित रखा गया है; और

(घ) इसी प्रकार रबी विपणन के कुल कितने प्रस्ताव मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क)**: खरीफ विपणन मौसम 2001 से मध्‍य प्रदेश सरकार से प्राप्‍त धान/चावल की खरीद के लिए प्रासंगिक खर्चों को अंतिम रूप देने के 6 प्रस्‍ताव और मोटे अनाजों की खरीद के लिए एक प्रस्‍ताव आज की तारीख में इस विभाग में लंबित है।

**(ख)**: विभाग में उपलब्‍ध रिकार्ड के अनुसार इन प्रस्‍तावों में 353.50 करोड़ रुपये का दावा किया गया है।

**(ग)**: खरीफ विपणन मौसम 2001-02 से 2006-07 तक के लिए चावल के प्रासंगिक खर्चों और खरीफ विपणन मौसम 2007-08 के लिए मोटे अनाज के प्रासंगिक खर्चों को अंतिम रूप देने के प्रस्‍ताव लंबित है। मौजूदा पद्धति के अनुसार प्रासंगिक प्रभारों को राज्‍य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा प्रस्‍तुत लेखापरीक्षित लेखाओं और अन्‍य समर्थक दस्‍तावेजों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम से परामर्श करते हुए व्‍यापक जांच करने के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। अंतिम रूप देने से पहले विवादित मुद्दों, यदि कोई हो, पर राज्‍य सरकारों के साथ चर्चा की जाती है। राज्‍य एजेंसियों के लिए प्रत्‍येक फसल मौसम की समाप्‍ति के बाद लेखापरीक्षित लेखे प्रस्‍तुत करने अपेक्षित होते हैं। अंतिम रूप देने में विलम्‍ब होने के मुख्‍य कारण राज्‍य द्वारा दावे विलम्‍ब से प्रस्‍तुत करना, एक बार में ही कई वर्षों के दावे प्रस्‍तुत करना, राज्‍य द्वारा अपूर्ण सूचना/दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करना आदि है।

**(घ)**: रबी विपणन मौसम 2007-08 और 2008-09 के लिए गेहूं की खरीद और वितरण के लिए प्रासंगिक खर्चों को अंतिम रूप देने के 2 प्रस्‍ताव मध्‍य प्रदेश सरकार से प्राप्‍त हुए हैं। रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए राज्‍य द्वारा अतिरिक्‍त दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने के बाद इस मुद्दे पर सितम्‍बर, 2011 में राज्‍य सरकार के साथ विस्‍तृत चर्चा की गई थी। रबी विपणन मौसम 2008-09 के लिए राज्‍य सरकार ने जुलाई, 2011 में लेखापरीक्षित लेखे प्रस्‍तुत किए जिन्‍हें विभाग में जांच करने से पहले टिप्‍पणियों हेतु भारतीय खाद्य निगम को भेजा गया है।

...........